देहरादून (उत्तराखण्ड)
रविवार 01.06.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस लागू की जाएंगी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आम लोगों तक कम कीमत पर आसानी के साथ बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
- भारतीय सेना ने देश भर में प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के आकलन के लिए क्षेत्र परीक्षण किए।
- लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा– उत्तराखंड के डिप्लोमा इंजीनियर्स, प्रदेश की प्रगति के मजबूत आधार।

ड्रग टेक–बैक साइट्स स्थापना

उत्तराखंड सरकार, दवाओं के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की गाइडलाइंस लागू करने जा रही है। यह कदम राज्य को 'हरित स्वास्थ्य प्रणाली' की ओर ले जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत दवाओं के निर्माण से लेकर उनके उपभोग और सुरक्षित निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत राज्य के शहरी, अर्ध–शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप से 'ड्रग टेक–बैक साइट्स' स्थापित की जाएंगी, जहां आम नागरिक अपने घरों में पड़ी एक्सपायर्ड या अनुपयोगी दवाएं जमा करा सकेंगे। इन दवाओं को अनुमोदित प्रोसेसिंग यूनिट्स में वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। यह प्रणाली विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुरूप होगी।
ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत सभी पक्षों की जवाबदेही तय की जाएगी। निर्माता कंपनियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, अस्पतालों और उपभोक्ताओं को इस प्रणाली का पालन करना होगा। सरकार इस दिशा में जन–जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि लोग इस प्रणाली में भागीदार बनें और दवाओं के गलत तरीके से निस्तारण के कारण होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा जा सके।

ऊर्जा समीक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में देहरादून स्थित उत्तराखंड जल विद्युत निगम सभागार में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूजेवीएनएल, पिटकुल और यूपीसीएल के प्रगति कार्यों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आम लोगों तक स्वच्छ, सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक, पर्यावरणीय और वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि किसी भी परियोजना में कोई बाधा न आए। बैठक के दौरान परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और केंद्र व राज्य एजेंसियों से समन्वय कर समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने तीनों निगमों को निर्देशित किया कि वे अपने–अपने प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत, देरी के कारण बढ़ी लागत और ऊर्जा दक्षता में नुकसान की जानकारी के साथ व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें। बैठक में बताया गया कि राज्य गठन के समय प्रदेश की विद्युत क्षमता एक हजार एक सौ मेगावाट थी, जो अब बढ़कर चार हजार दो सौ चौसठ मेगावाट हो चुकी है।

स्कूल बस सौगाता

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने डोईवाला स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल भोगपुर, दाबड़ा को एक नई स्कूल बस की सौगात दी। यह बस राइफल क्लब फंड और सीएसआर के माध्यम से दो महीने के भीतर उपलब्ध कराई गई है, जिससे अब दूर–दराज से आने वाले बच्चों को स्कूल तक आने–जाने में सुविधा होगी। स्कूल में 95 बच्चे पढ़ते हैं, जो 10 से 12 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों से आते हैं। परिवहन की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने स्वयं पहल करते हुए यह सुविधा उपलब्ध कराई। इस अवसर पर उन्होंने सभी 95 छात्रों को अपने स्तर से स्कूल शूज भी भेंट किए।

श्री बंसल कहा कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार लगातार तत्पर है। उन्होंने बताया कि 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' के तहत जिले के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल स्क्रीन, फर्नीचर और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं, असहाय और अनाथ बालिकाओं के लिए संचालित 'प्रोजेक्ट नंदा–सुनंदा' पहले से ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है।

बहुउद्देशीय शिविर

चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड के दूरस्थ गांव टेंटुणा में कल जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। टेंटुणा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज लाटूगैर में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों द्वारा कुल 112 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही जिला विकास अधिकारी के.के पंत द्वारा किया गया।

शिविर में ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं रखीं। पूर्व प्रधान चंद्र सिंह ने गांव में आंगनबाड़ी भवन के अभाव की समस्या उठाई। शिविर में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, राजस्व, पशुपालन, कृषि, उद्यान सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और ग्रामीणों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 90 लोगों की जांच कर मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं और होम्योपैथिक विभाग ने 52 जबकि आयुर्वेदिक विभाग ने 37 लोगों की जांच की।

परीक्षण

भारतीय सेना देश के प्रमुख स्थानों पर अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों के परीक्षण कर रही है। इसमें पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, बबिना फील्ड फायरिंग रेंज और जोशीमठ शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि इन क्षेत्रीय परीक्षणों को युद्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार 2014 से ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर बल दे रही है। नई दिल्ली में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने स्वदेशी वस्तुओं और अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों के आयात सहित रक्षा खरीद में लगातार निवेश किया है।

वर्चुअल संबोधन

लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड के डिप्लोमा इंजीनियर्स प्रदेश की प्रगति के मजबूत आधार हैं। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स विषम भौगोलिक परिस्थितियों में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य कर सड़कों, पुलों, जलापूर्ति, सिंचाई और भवन निर्माण जैसे कार्यों में बुनियादी भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र, नींबूवाला गढ़ीकैंट में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ, लोक निर्माण विभाग के द्वादश सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में श्री महाराज ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि विभागीय पुनर्गठन के प्रस्ताव में विभाग की आवश्यकता के अनुसार कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य पदों को बढ़ाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार अभियंताओं को सम्मान, सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रदेश में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता बनी रहे।

सुरक्षित यातायात

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में शहरी पुनर्विकास और पार्किंग योजना को लेकर बैठक ली। इस दौरान एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत चार साल पुराने प्रजेंटेशन पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को व्यवहारिक और अद्यतन योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सुगम सुरक्षित यातायात के संकल्प को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अब हर शनिवार वह स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मौजूदा योजनाएं भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। शहर के सभी प्रमुख चौराहों, जंक्शनों और क्रॉसिंग को बेहतर किया जाए। ऑन स्ट्रीट, ऑफ स्ट्रीट, मल्टीलेवल ऑटोमेटेड या सिविल पार्किंग की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि धनराशि की व्यवस्था प्रशासन करेगा लेकिन विभाग प्राथमिकता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें और हर सप्ताह इसकी प्रगति की जानकारी दें।

विश्व पर्यावरण दिवस– तैयारियां

विश्व पर्यावरण दिवस के सफल आयोजन के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए और जिला स्तर पर व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 जून को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पैदल कार्यालय आने तथा 4 जून को समूह में न्यूनतम वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही आज से 5 जून तक प्रतिदिन शाम साढे छह से साढे सात बजे तक 'अर्थ ऑवर' मनाते हुए आवासीय परिसरों में न्यूनतम विद्युत उपकरणों के उपयोग के निर्देश दिए।

उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में पौधरोपण अभियान, गाड़–गदेरों, पर्यटन और धार्मिक स्थलों, जल स्रोतों और श्रीनगर व यमकेश्वर के नदी घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। लैंसडौन के चिनबो, यमकेश्वर के पटना जल प्रपात और दुगड्डा मंदिर के आसपास भी विशेष सफाई अभियान संचालित करने को कहा गया है।

और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

उत्तराखंड में आपदा मित्र की तर्ज पर रखी जाएंगी आपदा सखी– इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने की घोषणा।

पदोन्नति न होने के विरोध में शिक्षक 16 जून को देंगे धरना– इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है–राजकीय शिक्षक संघ की शिक्षा महानिदेशक के साथ हुई बैठक में शिक्षकों ने पदोन्नति और तबादलों को लेकर रखी मांग।

उत्तराखंड में पदोन्नत हुए 57 दरोगा बने निरीक्षक, वरिष्ठ अधिकारियों ने लगाए स्टार– इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण लिखता है– लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे थे दरोगा।

पंचायतों में प्रशासकों को लेकर असमंजस बरकरार– इस शीर्षक के साथ हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है– राजभवन मे अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर विधायी और पंचायती राज विभाग से मांगा स्पष्टीकरण...